विभिन्न स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण और रोज़गार उन्मुखी शिक्षा की आवश्यकता

अनिल बाबू*

वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए सरकार और शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा आमूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। वहीं सरकार शिक्षा को कौशल के साथ जोड़कर छात्रों को हुनरमंद बनाने का प्रयास बड़े पैमाने पर कर रही है। देश की विभिन्न स्किल डेवलपमेंट ऐजेंसियाँ विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को हुनरमंद बनाकर रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही हैं। स्किल विशेषज्ञों का मानना है कि स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से छात्रों की बुनियादी मानसिक क्षमताओं को विकसित कर उनके अंदर मल्टीडायमेंशनल पर्सनलिटी डेवलप कर सकते हैं। वर्तमान स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में शिक्षा के स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाकर संस्थानों को किताबी ज्ञान के बजाय व्यावहारिक ज्ञान पर ज़्यादा फ़ोकस करना होगा। हम छात्रों को सीमित भूमिकाओं के लिए तैयार न करके, उनमें क्रिएटिविटी, टीमवर्क, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, क्यूरोसिटी आदि विकसित करें। ताकि वे अपनी क्षमता, योग्यता एवं रुचि के अनुसार रोज़गार प्राप्त कर सकें।

प्रस्तावना

वर्तमान भारतीय परिदृश्य शिक्षा जगत में छात्र-छात्राओं की अनेक उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा है, परंतु बदलते वातावरण में शिक्षण संस्थाओं में अनेक ऐसी घटनाएँ देखी जा रही हैं, जो बालकों के अंदर पनप रही निषेधात्मक प्रवृत्तियों को प्रदर्शित कर रही हैं। इन निषेधात्मक प्रवृत्तियों का पनपना हमें यह सोचने को विवश करता है कि क्या शिक्षण प्रक्रिया में कुशल निर्देशन, कौशलयुक्त शिक्षा, परिपक्व मार्गदर्शन एवं ज्ञान हस्तांतरण की प्रक्रिया में कहीं

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, मंदसौर, (म.प्र.) 458001

हमसे चूक तो नहीं हो रही है। क्योंकि आधुनिक युग इतना बहुआयामी विकास समेटे हुए है कि इसको परिभाषित करना कठिन है। कभी इसे विज्ञान एवं तकनीकी युग तो कभी आंतरिक सूचना क्रांति का युग कहा जाता है। इस आधुनिक युग में जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन देखा जा सकता है। हमने अनके सुविधाएँ विकसित की हैं, किंतु जीवन सरल होने की अपेक्षा और अधिक जटिल हो गया है। हाथ की जगह पर मशीन, रोबोट, कंप्यूटर काम करने लगे हैं, आधुनिक युग में जीवन की बढ़ती हुई जटिलताओं के कारण ऐसे बाहरी सहयोग की आवयकता अब और भी अधिक अनुभव की जा रही है जो कि बुद्धिमत्तापूर्ण चयन करने एवं उपयुक्त आत्मनिर्णय विकसित करने हेतु व्यक्ति को समर्थ बनाए। इस संपूर्ण प्रक्रिया में स्किल डेवलपमेंट ऐजेंसियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में युवाओं में स्किल विकास के लिए अनेक भारतीय स्किल ऐजेंसियाँ, जैसे– नेशनल स्किल डेवलपमेंट ऐजेंसी (National Skill Development Agency) नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (The National Skill Developemnt Corporation), नेशनल स्किल सर्टीफ़िकेशन एंड मोनेटरी रिवार्ड स्कीम (The National Skill Certification and Monetary Reward Scheme), नेशनल स्किलस क्वालीफ़िकेशनस फ्रेमवर्क (National Skills Qualifications Framewrok), नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरडीनेशन बोर्ड (National Skill Development Coordination Board), मिनिस्ट्री ऑफ़ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रिन्योरशिप (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) कार्यरत हैं, कुछ राज्यस्तरीय स्किल डेवलपमेंट ऐजेंसियाँ – राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC), मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट), भोपाल, सामुदायिक कौशल पार्क, केरल इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों, जैसे – एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, फ़ूड प्रोसेसिंग, (Food Processinig) ऑटोमोबाइल एंड कम्पोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, टेक्सटाइल एंड गारमेंट, केमीकल एंड फ़ार्मासुटिकल, लेदर एंड लेदर गुड्स, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रशन, हेन्डलूम्स एंड हेन्डीक्राफ्ट्स, आई.टी. एंड सॉफ़्टवेयर, आई.टी.ई.एस. एंड बी.पी.ओ, टूरिज़्म एंड ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन एंड पेकिंग, रियल एस्टेट, हेल्थकेयर, बैंकिग, फ़ाइनेंस, मीडिया, एंटरटेनमेंट, सोलर एनर्जी, होटल मैनेजमेंट, मोबाइल रिपेयरिंग, हाउस होल्ड रिपेयरिंग, हॉर्टीकल्चर एवं ऐनीमेशन इत्यादि क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि यदि प्रारंभ से ही बच्चों में इस तरह के कौशल विकसित किए जाएँ जो भविष्य में उनके लिए रोज़गार के अवसर मुहैया कराएँ, तो निश्चित ही भारत की अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया जा सकता है। स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों में वह लौ जगा सकते हैं, जहाँ वे सायबर युग के साथ कदम मिलाकर कर मल्टीडायमेनशनल पर्सनलिटी डेवलप कर सकें।

रोज़गार के लिए देश में बढ़ते कदम के साथ स्किल इंडिया का आगाज़

वर्तमान समय में देश के करोड़ों लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए भारत सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन में स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया है। मौजूदा वित्त वर्ष में स्किल इंडिया मिशन के लिए सरकार ने 5040 करोड़ राशि का आवंटन किया है। वर्तमान समय में देश में केवल 3.5 फ़ीसदी लोग हुनरमंद हैं। देश को विकासशील बनाने के लिए बड़े पैमाने पर हुनरमंद लोगों की ज़रूरत के साथ-साथ देश के युवाओं के हुनर को पहचानने की आवश्यकता है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत 2022 तक करीब 50 करोड़ लोगों को हुनरमंद बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

नेशनल स्किल डेवलपमेंट योजना से 160 ट्रेनिंग पार्टनर्स और 1722 ट्रेनर्स को जोड़ा गया है। इसके तहत करीब 35 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। देश में करीब 20 सरकारी संस्थाएँ और भारतीय रेलवे ने 450 स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभ किए हैं। देश में जानकारों का मानना है कि देश में मैन्युफ़ैक्चरिंग सेगमेंट में स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जिसके तहत अगले कुछ साल में बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर युवाओं को मिलेंगे। इस दिशा में टाटा समूह द्वारा यूके इंडिया बिज़नेस काउंसिल (UK India Bussiness council) के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की है, जिसके तहत देश में स्किल्स ट्रेनिंग मुहैया करवाकर प्रशिक्षित और रोज़गार के काबिल कर्मचारी तैयार किए जाएँगे।

हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भारतीय युवाओं को जॉब आधारित ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कनाडा के शैक्षणिक संस्थानों के साथ 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य प्रशिक्षुओं के लिए बेहतरीन शिक्षा प्रदान करना और स्किल डेवलपमेंट के लिए कनाडा के स्किल काउंसिल के साथ काम करना है। इन समझौतों के तहत किसी एक विशिष्ट क्षेत्र, जैसे— एविएशन, हेल्थकेयर या एग्रीकल्चर पर फ़ोकस करने वाले भारतीय पार्टनर के साथ कनाडा के एक कॉलेज को जोड़ा जाएगा। एन.एस.डी.सी. के इस कदम से भारतीय युवाओं को न सिर्फ़ देश की, बल्कि विदेशी इंडस्ट्री के लिए जॉब तैयार करने में मदद मिलेगी। (स्रोत – कॅरिअर मंत्र, *दैनिक भास्कर*, रतलाम, मंगलवार,19 मई 2015)

वर्तमान स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बिना निरर्थक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम

देश में शिक्षा की बदतर हालत के बारे में सभी जानते हैं। स्कूली शिक्षा का सर्वे करने वाली सालाना 'असर' रिपोर्ट में पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा के गिरते स्तर पर लगातार चिंतनीय तथ्य सामने आ रहे हैं। वर्ष 2014–रिपोर्ट में बताया गया है कि पाँचवीं कक्षा के अधिकांश छात्र दूसरी कक्षा का पाठ भी नहीं पढ़ सकते। यह सहज ही कल्पना की जा सकती है कि हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षाओं के लिए वे कितने तैयार होंगे। कक्षा में टीचर उपस्थित नहीं होते। छोटी कक्षाओं में आने में भाषा और गणित की पढ़ाई का स्तर इतना खराब है कि बड़ी कक्षा में आने पर छात्र

को कुछ समझ नहीं आता और वह स्कूल जाना छोड़ देते हैं। नतीजा, स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा है। स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सैकड़ों कमियाँ हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ज़िम्मेदार लोग तो समस्या को पहचाने से ही इंकार करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल इंडिया एवं स्किल इंडिया पर ज़ोर देकर बिलकुल सही किया है। सूचना प्रौद्योगिकी का फ़ायदा उठाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है। पूरा विश्व, यहाँ तक कि सबसे अविकसित राष्ट्र भी, बेहतर शिक्षा और ऊँची साक्षरता दर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश की युवा आबादी का फ़ायदा उठाने की बात करते हैं, लेकिन यदि करोड़ों अशिक्षित-अर्धशिक्षित युवा सड़कों पर घूमने लगें तो यह देश के लिए सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। वे किसी रोज़गार के लायक नहीं होगें और यह देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक होगा। देश के युवाओं को उचित निर्देशन एवं स्किल प्रशिक्षण की ज़रूरत है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। शिक्षा क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर बड़े पैमाने पर सुधारों की तत्काल आवश्यकता है।

प्राथमिक विद्यालयों में क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन के आधार पर तैयार होंगे रोज़गार के अवसर

देश के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की संख्या में अंतर कम होता जा रहा है। प्राथमिक स्कूलों में हम जेंडर पैरिटी हासिल कर चुके हैं और सेकंडरी; (Secondary) स्तर पर भी इसके काफ़ी करीब हैं। यूनेस्कों की ताज़ा ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत वर्ष 2015 में स्कूली शिक्षा में लिंग समानता हासिल करने वाला दक्षिण पश्चिम एशिया में पहला देश होगा। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर एजुकेशन फ़ॉर ऑल का लक्ष्य पाने की ओर भी भारत ने कदम बढ़ा दिए हैं। प्राइमरी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन में भी सुधार हुआ है, लेकिन छात्रों का कमज़ोर लर्निंग स्तर अब भी चुनौती बना हुआ है। यूनेस्को के अलावा इस साल की 'असर' रिपोर्ट में भी बताया गया है कि दूसरी और चौथी कक्षाओं में लड़के और लड़कियों

राज्य	दूसरी कक्षा		चौथी कक्षा	
	छात्र	छात्राएँ	छात्र	छात्राएँ
आंध्र प्रदेश	45.4	54.6	45.3	54.7
असम	50.4	49.6	49.9	50.1
हिमाचल प्रदेश	51.5	48.5	51.5	48.5
झारखंड	50.3	49.7	47.5	52.5
राजस्थान	52.2	47.8	54.2	45.8

स्रोत – ASER 2014 की 10वीं रिपोर्ट

की संख्या लगभग एक जैसी है। छात्राओं का सबसे ज़्यादा अनुपात आंध्र प्रदेश में हैं, कई राज्यों में लड़कियों की तादात लड़कों से ज़्यादा है।

एनुअल स्टेट्स ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट या असर, 2014 के अंतर्गत 577 जिलों और 16.497 गांवों के करीब 5.70 लाख बच्चों को लिया गया। असर की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत के 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के 96.7 प्रतिशत बच्चे जो स्कूलों में नामांकित हैं, उन बच्चों में से 71 प्रतिशत ही विद्यालय जाते हैं। बेशक, वहाँ क्या होता है, यह बिलकुल अलग बात है। लेकिन स्कूली मूलभूत सुविधाओं में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। मध्याह्न भोजन की योजना 85 फ़ीसदी से ज़्यादा स्कूलों में उपलब्ध है, करीब 75 फ़ीसदी ग्रामीण स्कूलों में पीने का पानी उपलब्ध है, 65 फ़ीसदी स्कूल में उपयोग करने योग्य शौचालय हैं। प्राथमिक स्कूलों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को साक्षर नहीं, शिक्षित बनाना है। स्कूल इस मामले में क्या कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने के बुनियादी स्तर के बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार—

- पाँचवी कक्षा के लगभग आधे बच्चे सरल हिंदी के वाक्य नहीं पढ़ सकते जो दूसरी कक्षा में सिखाए जाते हैं।
- पाँचवी कक्षा के लगभग आधे बच्चे बुनियादी संक्रियाएँ, जैसे — दो अंकों वाला घटाव, जोड़, गुणा, भाग आदि नहीं कर सकते, जो दूसरी कक्षा में सिखाया जाता है।
- कक्षा आठवीं के आधे बच्चे साधारण से भाग नहीं कर सकते जो पाँचवी कक्षा में सिखाए जाते हैं।
- दूसरी कक्षा के लगभग 33 प्रतिशत बच्चे अक्षर भी नहीं पहचान सकते।

इस रिपोर्ट के अुनसार देशभर के स्कूलों में लर्निंग का स्तर बेहद खराब है। उन राज्यों में लर्निंग का स्तर बेहतर है, जहाँ शिक्षित माता-पिता का अनुपात ज़्यादा है।

इन तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें शिक्षा व्यवस्था में संशोधन एवं सुधार की नितांत आवश्यकता है। स्कूल में पाँच साल बिताने के बाद हमारे स्कूली छात्र सामान्य वाक्य नहीं पढ़ सकते या साधारण जोड़-घटाव नहीं कर सकते। क्या हम केवल स्कूलों में नामांकन संख्या में वृद्धि और मध्याह्न भोजन के आँकड़ों का ही जश्न मनाते रहेंगे और स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता को भूल जाएँगे? आँकड़ों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि यदि आधारभूत कौशल शुरुआत में ही अच्छी तरह सीख नहीं लिए जाते तो बाद के वर्षों में उन्हें सीखा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि इन आंकड़ों को बदला नही जा सकता। ऐसा भी नहीं कि इस तरह की समस्या भारत में है, न ही यह बात केवल हमारे देश पर लागू होती है, वरन् अमेरिका जैसे विकसित देश भी बच्चों की पढ़ने की अक्षमता को लेकर चिंतित हैं। अमेरिका में पठन कौशल में सुधार हेतु "नो चाइल्ड लैफ़्ट बीहाइंड लॉ 2002"; (No child left behind law 2002) के अनुसमर्थन में रीडिंग फ़र्स्ट कार्यक्रम लाया गया था, जिसमें वहाँ पर राज्यों को प्राथमिक कक्षाओं के पठन कौशल विकास पर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने हेतु सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पठन कौशल के

मूल्यांकन हेतु मानक निर्धारित किए गए। यह मानक भी समान न होकर विभिन्न राज्यों हेतु भिन्न-भिन्न हैं। मौखिक रूप से धाराप्रवाह ढंग से पढ़ने की गति ग्रेड-1 में 60 शब्द प्रति मिनट, ग्रेड-2 में 94 शब्द तथा ग्रेड-3 में 114 शब्द प्रति मिनट रखी गयी। इस तरह समझकर पढ़ने हेतु मानक निर्धारित किए गए। हम सब मिलकर इस गंभीर समस्या का समाधान कर सकते हैं।

स्वीडन में 1999 में कुनस्काप्सकोलान एडवेंचर के.ई.डी. प्रोग्राम (The kunskapsskolan Adventure KED Programme) की स्थापना की गई थी, जिसका मकसद ऐसे स्कूल तैयार करना था, जहाँ पर्सनलाइज़्ड ट्रेनिंग, नये आइडियाज़ और इनोवेटिव टीचिंग का माहौल तैयार हो। के.ई.डी. प्रोग्राम शुरू करने का उद्देश्य था कि हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत इच्छा और ज़रूरतों पर ध्यान देना और शिक्षा को हर विद्यार्थी की ज़रूरत के हिसाब से उपलब्ध कराना। हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाना चाहिए और प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में कौशलों के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। आज देश में अच्छे शिक्षकों की कमी है, लेकिन हम तकनीकी का उपयोग कर कुछ स्कूलों को एकजुट करें और वर्चुअल क्लास तथा वास्तविक कक्षाओं का मिला-जुला इस्तेमाल करें तो कार्यकुशलता हासिल करने की दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है।

ग्रेड सिस्टम एवं पाठ्यपुस्तकों में बदलाव की आवश्यकता है। ग्रेड स्तर के लिए तैयार की गई पाठ्यपुस्तकें इन बच्चों की कोई मदद नहीं कर सकतीं, जब तक कि वे पढ़ने और समझने में सक्षम नहीं हो जाते। बच्चों को बोलने, चर्चा करने, अपने विचार व्यक्त करने और साथ मिलकर सवालों को हल करने के लिए प्रेरित करके उनकी बुनियादी क्षमताओं में सुधार किया जा सकता है।

देश को एजुकेशन सुपरपावर बनाने के लिए चाहिए स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन

वर्ष 1951 में देश की केवल 16 फ़ीसदी आबादी शिक्षित थी। वर्ष 2011 तक यह आँकड़ा 74 फ़ीसदी से ज़्यादा हो चुका था। आज़ादी के बाद आधारभूत संरचनाओं के विस्तार और कानूनी प्रावधानों के ज़रिए सबको आसानी से शिक्षा उपलब्ध कराने का अभियान शुरू हुआ था। 1950 में देश का नया संविधान लागू होने के बाद भारत एजुकेशन सुपरपावर बनने की राह पर अग्रसर है। यदि देश के अभिभावक अपने बच्चों को किसी कौशल को सीखने के लिए प्रेरित करें तो हम भविष्य के भारत को स्किल सुपरपावर बना सकते हैं।

देश को एजुकेशन सुपरपावर बनाने में निम्न कारकों की अहम भूमिका होगी—

एनरॉलमेंट — 1950-51 में 100 में से 42.6 बच्चे ही स्कूल जाते थे। आज प्राइमरी स्कूलों में एनरॉलमेंट रेशो करीब 96 फ़ीसदी और सेकंडरी स्कूलों में 40 फ़ीसदी है। उच्च शिक्षा में यह अब भी 19 फ़ीसदी है, लेकिन वर्ष 2020 तक इसके 30 फ़ीसदी होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के अनुसार चार करोड़ से ज़्यादा छात्र हायर एजुकेशन संस्थानों में पढ़ेंगे और वर्तमान समय में करीब दो करोड़

60 लाख छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। संख्या के लिहाज़ से भारत में इंग्लैंड के मुकाबले छह गुना ज़्यादा ग्रेजुएट हर साल तैयार होते हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर — नया संविधान लागू होने के समय देश में केवल दो लाख 10 हज़ार प्राइमरी और 14 हज़ार मिडिल स्कूल थे। आज देश के करीब 13 लाख स्कूलों में 23 करोड़ से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। 85 फ़ीसदी से ज़्यादा आबादी के लिए एक किलोमीटर से कम दूरी पर प्राइमरी स्कूल उपलब्ध हैं। वर्ष 1950 में हायर एजुकेशन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या केवल चार लाख थी। आज हर साल करीब 20 लाख छात्र इनमें प्रवेश लेते हैं। पिछले 65 सालों में देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 18 गुना और कॉलेजों की संख्या 35 गुना बढ़ी है। (स्रोत — आँकड़े ओ.ई.सी.डी. की रिपोर्ट)

शिक्षा पर व्यय — अंग्रेज़ी शासन के समय शिक्षा केवल संभ्रांत वर्ग के लोगों के लिए थी। स्वतंत्रता के बाद से हर वर्ग के लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने इस पर खर्च में लगातार वृद्धि की है। वर्ष 1950-51 में शिक्षा पर कुल खर्च केवल 10,080 करोड़ रुपये था जो जी.डी.पी. का 0.64 फ़ीसदी था। फ़िलहाल यह तीन फ़ीसदी के करीब है। 2007-12 के बीच ही हर साल शिक्षा पर होने वाले खर्च में 25 फ़ीसदी वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 के बजट में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 28,258 करोड़ रुपये फ़ंड निर्धारित किया गया है। (स्रोत — सर्व शिक्षा अभियान, बजट 2014-15)

विदेशी शिक्षा — भारत से बेहतर शिक्षा के लिए हर साल तीन लाख से ज़्यादा छात्र विदेश जाते हैं। इसे और सुलभ बनाने के लिए सरकार फ़ॉरेन एजुकेशन प्रोवाइडर्स विधेयक पास करने की तैयारी कर रही है। इससे विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिल जाएगी और छात्र को देश में ही उच्चस्तरीय शिक्षा उपलब्ध होगी।

स्किल एजुकेशन — देश की 54 फ़ीसदी से ज़्यादा आबादी केवल 25 वर्ष से कम उम्र की है और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अनुसार वर्ष 2022 तक हर साल करीब 1 करोड़ 28 लाख लोग वर्कफ़ोर्स में शामिल होंगे। चीन के बाद भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्कफ़ोर्स वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन 10 फ़ीसदी लोगों के पास ही वोकेशनल ट्रेनिंग है, जबकि करीब 90 फ़ीसदी नौकरियों के लिए यह ज़रूरी है। सरकार ने 2022 तक 50 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन एजेंसियों की बहुलता और को-ऑर्डिनेशन की कमी के चलते यह योजना लक्ष्य से काफ़ी पीछे है। इस साल के बजट में सरकार ने नेशनल स्किल मिशन की घोषणा और इसे 'मेक इन इंडिया' से जोड़ने की घोषणा की है।

रोज़गार के लिए परफ़ेक्ट बनाने होंगे मौजूदा ग्रेजुएट्स

वर्तमान स्थिति को मद्देनज़र रखकर कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, जिससे देश में रोज़गार के अवसर दिनों-दिन बढ़ रहे हैं। सरकार की पहल से देश में वोकेशनल यूनिवर्सिटीज़ की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन इन सब के

बीच आज यूनिवर्सिटीज़ अभी महज़ ग्रेजुएट ही तैयार कर रही हैं। उन विद्यार्थियों में स्किल्ड वर्कफ़ोर्स नहीं है। रिक्रूटमेंट सेक्टर से जुड़ी करियर बिल्डर इंडिया के ताज़ा सर्वे में यह तथ्य सामने आए हैं (400 से ज़्यादा कंपनियों के बीच यह सर्वे हुआ) कि बदलते माहौल में भी संस्थान व्यावहारिक ज्ञान के बजाय किताबी ज्ञान पर ही ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। 65 फ़ीसदी कंपनियों का कहना है कि यूनिवर्सिटीज़ सीमित भूमिकाओं के लिए छात्रों को तैयार कर पा रही हैं। आठ फ़ीसदी कंपनियाँ मानती है कि छात्रों को इंडस्ट्री के मुताबिक तैयार नहीं किया जा रहा है। वर्तमान के छात्रों में क्रिएटिविटी, टीमवर्क, कम्युनिकेशन, लीडरशिप इत्यादि स्किल्स की कमी देखी जा रही है। तथ्यों से जुड़े विशेषज्ञो का मानना है कि यूनिवर्सिटीज़ 68 प्रतिशत छात्रों को प्रैक्टिकल के बजाए थ्योरी पर ज़ोर दे रही हैं 57 प्रतिशत यूनिवर्सिटीज़ छात्रों की टेक्नीकल (Technical) और सॉफ़्ट स्किल्स पर ध्यान नहीं दे रही है और 47 प्रतिशत छात्र बदलती तकनीकी के साथ अपडेट नहीं हैं।

देश के कई उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में फ़िलहाल 30 से 40 फ़ीसदी शिक्षकों की सीटें खाली पड़ी हैं। एन.एस.सी.एस. द्वारा किए गए एक सर्वे की की रिपोर्ट बताती है कि डिग्री ले लेने के बाद भी केवल 25 फ़ीसदी टेक्निकल ग्रेजुएट और लगभग 15 प्रतिशत अन्य स्नातक आई.टी. और संबंधित क्षेत्रों में काम करने लायक होते हैं। यह एक मुख्य वजह है कि अब ज़्यादातर ग्रेजुएट्स वर्कफ़ोर्स के काबिल साबित नहीं हो रहे हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक्टिव लर्निंग के लिए देश में बिज़नेस स्कूल फ़्लिप्ड क्लासरूम बढ़ रहे हैं। जहाँ पांरपरिक मॉडल की बजाय घर पर ऑनलाइन लेक्चर सुनकर क्लास के टाइम का उपयोग साझा लर्निंग के लिए किया जाता है। आई.एस.बी. पहला मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, जिसने फ़्लिप्ड क्लासरूम की शुरुआत की। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी भी टॉक एंड चॉक टीचिंग मेथड के बजाय टेक्नोलॉजी आधारित एक्टिव लर्निंग पर काम कर चुकी है। विदेशी यूनिवर्सिटीज़ इस मामले में आगे हैं, सिंगापुर के ड्यूक-एन.यू.एस. मेडिकल स्कूल मे स्टूडेंट्स क्लास में आने से पहले ऑनलाइन लेक्चर्स से तैयारी करके आते हैं, फ़िर क्लास में आकर टेस्ट देते हैं, 15 मिनट का लेक्चर लेते हैं और उसके बाद फ़िर से टेस्ट देते हैं। उसके बाद वे इस नॉलेज का इस्तेमाल छोटी-छोटी टीम्स में केस प्रॉबलम्स को सुलझाने के लिए करते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि लेक्चर्स के दौरान हर दस मिनट में लंबे भाषण को एक्टिव टीचिंग टेक्नीक्स के साथ बदलना ज़्यादा प्रभावी होता है। कुछ अन्य अध्ययनों में पाया गया कि पारंपरिक लेक्चर्स की तुलना में एक्टिव लर्निंग का इस्तेमाल करने वाले छात्रों का स्कोर ज़्यादा बेहतर होता है।

वोकेशनल प्रशिक्षण के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता

वोकेशनल ट्रेनिंग के क्षेत्र में सरकार को महत्वपूर्ण संशोधन और सुधार की आवश्यकता है। वोकेशनल प्रशिक्षण के क्षेत्र में हम कितने पिछड़े हैं, इस बात का अंदाज़ा इन आँकड़ों के आधार पर लगाया जा सकता है। जो निम्न प्रकार हैं –

कोरिया	जापान	जर्मनी	यूके	भारत
96%	80%	75%	68%	10%

स्रोत – नेशनल कॉउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT)

इन आकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वोकेशनल प्रशिक्षण के क्षेत्र में हम कितने पिछड़े हुए हैं। इसीलिए डिग्री होने के बावजूद हमें नौकरी नहीं मिलती है।

शिक्षा के हर सेक्टर में हुनरमंद लोगों की ज़रूरत है। स्किल इंडिया से अगले कुछ साल में बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे। सरकार की पहल से देश में वोकेशनल यूनिवर्सिटीज़ की संख्या भी बढ़ेगी। फ़िलहाल देश में ट्रेनिंग की ज़रूरत का केवल 30 फ़ीसदी ही मौजूद है, ऐसे में स्किल इंडिया में काफ़ी निवेश और वृद्धि के मौके नज़र आ रहे हैं। देश का करीब 65 फ़ीसदी वर्कफ़ोर्स फ़िलहाल कम स्किल वाले रोज़गार में है, लेकिन अर्थव्यवस्था के विकास के साथ वर्ष 2022 तक भारत के करीब 34 करोड़ 70 लाख स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होगी। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट मिशन को मेक इन इंडिया अभियान के साथ जोड़ने की घोषणा की है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से मंत्रालय बनाया है, लेकिन स्किल ट्रेनिंग का लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी क्षमता का विस्तार और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है।

निष्कर्ष

शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु शिक्षाविदों एवं सरकार को शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन की एक पहल करनी होगी। जब तक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार नहीं होगा, तब तक रोज़गार की संभावनाओं में भी बदलाव नहीं आयेगा। शिक्षा के माध्यम से छात्रों की मानसिक और बुनियादी क्षमताओं में परिवर्तन लाकर उन्हें कौशलयुक्त शिक्षा देनी होगी, इसके लिए शिक्षक ज्ञान के स्रोत की तरह नहीं, बल्कि फ़ैसिलिटेटर यानी मदद करने और सुगम बनाने वाले की तरह पेश आएँ। हम मेजर ध्यानचंद का आकलन उनके खेल कौशल से करते हैं, न कि उनकी डिग्री से। फ़िर बच्चों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर क्यों आँकते हैं? प्रत्येक बच्चे में एक निवेश प्रतिभा होती है। हर बच्चे को उसके कौशल के आधार गतिविधियों में भाग लेने के मौके दें। ताकि उनके अंदर छिपी कौशल प्रतिभा को ज़्यादा से ज़्यादा निखारा जा सके। शिक्षा को स्कूल के बाहरी जीवन या आस-पास की चीज़ों से जोड़ें और बच्चों की सहभागिता से उनके अनुभवों का दायरा बढ़ाएँ। बच्चों की गलतियों पर गोले लगाने या सज़ा देने के बजाय उनमें अपनी गलतियाँ स्वयं ढूँढ़ने और सुधारने का नज़रिया विकसित करें। जो उनके जीवनभर काम आने वाला है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम देश में शिक्षा के पूरे ढाँचे में ''सम्पूर्ण'' बदलाव लाने की वकालत करते थे। उनका मानना था कि युवाओं में ऐसे कौशल विकसित किए जाएँ जो भविष्य की चुनौतियों से निपटने में मददगार हों। इसमें एक और पहलू इसे सस्ता बनाना और देश की गरीब आबादी की पहुँच में लाना भी होगा।

संदर्भ

जोहन, हूवर. 2007. *टाइम मेनेजमेंट – सेट प्राइओरिटीज़ टू गेट द राइट थिंगस डन.* हार्पर कोलिन्स ई-बुक्स.

दैनिक भास्कर. ‘करिअर मंत्र’. रतलाम, बुधवार, 11 मार्च 2015.

____. सोमवार, 26 जनवरी 2015.

पाण्डे, रामेश्वरी. 2011. *एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया.* न्यू सेंचरी पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.

मेकलियन, रुपर्ट, जगन्नाथन, शांति, सारवी, जोको (संपादक). 2013. *स्किल्स डेवलपमेंट फ़ॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनएबल ग्रोथ इन डेवलपिंग एशिया-पेसिफ़िक.* स्प्रिंगर. नीदरलैंड्स.

मेहरोत्रा, संतोष. 2014. *इंडियासज़ स्किल चैलेंज– रिफ़ोर्मिंग वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू हारनेस द डेमोग्राफ़िक डिवाइडेंड.* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यू.एस.ए.

त्रिपाठी, प्रमोद कुमार. 2014. *स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया.* नेहा पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स.

http://asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER%202014/Press%20releases/pressreleasehindi.pdf

http://dise.in/Downloads/Elementary-STRC-2013-14/23.pdf

http://dise.in/ElementarySRC-2013-14.htm#

http://mhrd.gov.in/sites/upload files/mhrd/files/document-reports.part2.pdf

http://www.nsda.gov.in/

http://www.indiastat.com/education/6370/enrolments/6373/enrolmentinprimarybasicmiddleeducationclassesuptoviii/366798.stats.aspx

http://www.nuepa.org/publications.html

http://www.skilldevelopment.gov.in/